## बौद्धिक संपदा अधिकारों पर भारत और ब्रिटेन के मध्य द्विपक्षीय सहयोग पर संयुक्त आशय वक्तव्य

1. ब्रिटेन और भारत के सितम्बर, 2004 के संयुक्त घोषणा-पत्र ने भारत और ब्रिटेन को ब्रिटेन-भारत संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति (जेटको) संस्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध किया। ब्रिटेन-भारत संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति (जेटको) का प्रयोजन भारत और ब्रिटेन के बीच रणनीतिक आर्थिक संबंध विकसित करने तथा द्विपक्षीय व्यापार और निवेश बढ़ाने के मार्गों की पहचान करने में मदद करना है। जेटको के विचारणीय विषयों पर जनवरी, 2005 में भारत के वाणिज्य मंत्री श्री कमलनाथ तथा तत्कालीन ब्रिटिश सैक्रेट्री ऑफ स्टेट फॉर ट्रेड एंड इंडस्ट्री सुश्री पेट्रिशिया हेविट की संयुक्त अध्यक्षता में हुई मंत्री स्तर की उद्घाटन-बैठक पर सहमति बनी थी।

2. इस बैठक में बढ़े हुए व्यापार और/अथवा अनुसंधान और विकास सहित ज्ञान-आधारित उद्योगों और सेवाओं, निवेश, कृषि, अवसंरचना (ऊर्जा सहित) के लिए विशेष संभाव्यता की पेशकश के रूप में महत्वपूर्ण क्षेत्रों की श्रृंखला की पहचान की गई थी। इन क्षेत्रों में से सहयोगात्मक कार्यकलाप के जिस एक क्षेत्र का पता लगाया गया था:

   "....दोनों देशों के व्यापार सरोकारों और इनसे संबंधित व्यवहारिक उपाय अपनाने के संबंध में सरकार के नेतृत्व में आईपीआर मुद्दों की जांच करना।"

3. भावी सहयोग के लिए संभाव्य क्षेत्रों की सामान्य सूची निम्नलिखित है:
   i) पेटेंट और व्यापार चिह्न अधिकारियों का प्रशिक्षण और प्रबंधन,
   ii) पेटेंट और व्यापार चिह्न प्रतिनिधियों के व्यवसाय का विकास,
   iii) बौद्धिक संपदा के उल्लंघनों और उनके समाधान की छानबीन की बेहतर प्रथाओं और अनुभव की साझेदारी,
   iv) भारत के बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में अकादमिक योग्यता/शिक्षण/प्रशिक्षण सुविधाओं सहित विधि विद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में बौद्धिक संपदा विधि का शिक्षण। इसमें भारतीय शिक्षण संस्थाओं तथा ब्रिटेन में उनके प्रतिरूपों के बीच सहयोगात्मक अकादमिक कार्यक्रमों को सम्मिलित किया जा सकता है और
   v) उद्योग द्वारा बौद्धिक संपदा के इस्तेमाल में जागरूकता और समझ की वृद्धि।

**कार्यान्वयन**

4. समयोग के इन क्षेत्रों को यूके पेटेंट ऑफिस और भारतीय पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न महानियंत्रक कार्यालय द्वारा कार्यान्वित संयुक्त कार्यक्रम के जरिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

हस्ताक्षरित/-

भारत सरकार
के प्रतिनिधि

हस्ताक्षरित/-

यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड
सरकार के प्रतिनिधि